उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) (क) और (ख) मैसर्स जे० बी० मंगाराम एण्ड कम्पनी को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन पंजीकृत दो फैक्टरियां है—एक ग्वालियर में और दूसरी हैदराबाद में। मैसर्स जे० बी० मंगाराम के तीन अन्य एकक स्थापित हुए हैं जो तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची में हैं। वे ये हैं :—

(1) मैसर्स जीवन फूडस बम्बई फैक्टरी हैदराबाद में,

(2) मैसर्स मंगाराम एण्ड संस बम्बई, फैक्टरी बंगलौर में,

(3) मैसर्स इण्टरनेशनल फूड्स, बम्बई—फैक्टरी हैदराबाद में।

Proposal to stop Export of Nuclear know-how to other Countries

1293. SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government propose to stop export of nuclear know-how to foreign countries and if so, the reasons therefor;

(b) whether the U.S. Secretary of State has approached the Indian Government in this regard; and

(c) if so, the reaction of the Government of India in this regard?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS AND MINISTER OF SPACE (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) We shall continue to co-operate with friendly countries in consonance with the terms of the collaboration agreements entered into with them on the peaceful uses of atomic energy.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Clash between Security Forces and Mizo Hostiles on Burma-Mizoram Border

1294. SHRI H N. MUKERJEE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state

(a) whether there was a major clash between the security forces and Mizo Hostiles on the Burma-Mizoram Border recently;

(b) if so, the facts thereof, and

(c) the steps Government propose to take to pacify Mizo hostiles?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H MOHSIN): (a). No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Government do not consider any talks with the underground Mizos would be purposeful as long as the Mizo rebels adhere to their secessionist demand and continue their treasonable activities.

केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति

1295. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 3 अक्तूबर, 1974 के एक हिंदी दैनिक तथा दिनांक 12 अक्तूबर, 1974 के एक अन्य हिंदी दैनिक समाचार-पत्र में केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में हिंदी अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सम्पादक के नाम पत्रों की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां तो क्या इस बारे में सभी मंत्रालयों से पूछताछ की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले,

(ग) क्या पहले इसके लिए लिखित परीक्षा की व्यवस्था थी तथा बाद में लिखित

परीक्षा की व्यवस्था एक परिपत्र के द्वारा समाप्त की गई जिसे केवल कुछ ही मंत्रालयों को भेजा गया और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). यह रिक्त स्थान भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को परिपत्रित किया गया था जिसमें उक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रत्याशियों के लिए योग्यतायें और अनुभव निर्धारित किए गए थे। क्योंकि भर्ती तदर्थ आधार पर की जानी थी इसलिए कोई लिखित परीक्षा न लेने का निर्णय किया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि कोई अनियमितता नहीं की गई है।

ऊर्जा मंत्रालय के 'पावर विंग' में हिन्दी अधिकारी का पद भरने के बारे में अभ्यावेदन

1298. श्री चन्द्र शेखानी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनके मंत्रालय के 'पावर विंग' में हिंदी अधिकारी के पद को भरने हेतु लिए गए इन्टरव्यू तथा अपनाई गई अन्य प्रक्रिया के विरुद्ध बाहर के तथा मंत्रालय के कुछ उम्मीदवारों ने अभ्यावेदन भेजे थे,

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या आपत्तियां उठाई थी और उनके निराकरण के लिए क्या कार्यवाही की गई है,

(ग) क्या एक ही पद विज्ञापित किया गया और अब 13 सितम्बर, 1974 के इन्टरव्यू के आधार पर हिंदी अधिकारी के दो या तीन पद भरे जा रहे हैं, और

(घ) 'पवर विंग' द्वारा विज्ञापित तथा वहीं के चेयरमैन की अध्यक्षता में गठित बोर्ड द्वारा किए गए तथाकथित चयन के आधार पर मंत्रालय में हिंदी अधिकारी के पदों को क्यों भरा जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग) इस चयन के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इनमें मुख्य आपत्तियां ये थीं, कि साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्न एक समान नहीं थे और कोई लिखित परीक्षा नहीं ली गई। इन आपत्तियों को अमान्य पाया गया। इस समय, 13-9-1974 को हुए चयन के आधार पर हिन्दी अधिकारी के किसी और पद को भरने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Kakkad Hydro-Electric Scheme pending with Planning Commission for clearance

1297. SHRI R. BALAKRISHNA PILLAI: Will the Minister of PLANNING be pleased to state.

(a) whether Kakkad Hydro Electric Scheme is still pending clearance with the Planning Commission; and

(b) if so, the reasons for delay in giving clearance to it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNNG (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA). (a) and (b). Kerala State Government forwarded to the Planning Commission the project report for this scheme in April 1974 for installing two 35 MK sets at the Kakkad power house. The estimated cost of the scheme is Rs. 1568 lakhs. The project report is presently under technical examination in the concerned Ministries whereafter it will be considered by the Technical Advisory Committee. The Planning Commission will be able to consider the clearance of the scheme for inclusion in the Plan only after the